

53

FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

आपकी परिभाषा
23/9/19

APP-A
Crim-1

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

मैसर्स शांति एग्री. प्रा. लि. लु. मि. रा. मि. ए. पु. वि. जयराज सिंह
विरुद्ध आरेम 25 मा. शांति राजस्थान अजमेर

किस्म मुकदमा नम्बर सन् 2019 (53)
215 आरेम 25 एम 340/2019 (आम नोल्या)

2019/00340

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री दीपक पारीक एड. श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
23.9.19	<p>यह अपील श्री दीपक पारीक एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू के आदेश दिनांक 11.06.2019, प्रकरण संख्या 30/2019 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. अपील प्रस्तुत की अनुमति बाबत पेश किया है। अपील मियाद बाहर पेश की गई, जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पेश किया गया। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। जिस पर अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गई।</p> <p>अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि रेस्पोजेन्ट संख्या 01 से 02 ने एक वाद पत्र मय अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू के समक्ष पेश कर कथन कि जिसमें वर्णित किया कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 37 के आराजी खसरा नम्बर 772 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 774 रकबा 0.34 है0, खसरा नम्बर 810 रकबा 0.01 है., खसरा नम्बर 914/773 रकबा 1.09 है. कुल रकबा 1.54 है. भूमि वाकै ग्राम नोल्या तहसील दूदू में अवस्थित है जिसके साबिक खसरा नम्बर 3418/2 है जो राजस्व रिकार्ड में रेस्पोजेन्ट संख्या 3 से 05 के 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सा बरार दर्ज है लेकिन अप्रार्थी संख्या 3 के 1/3 हिस्से में से रेस्पोजेन्ट संख्या 3 का 1/3 हिस्सा है। इसी अनुसार रेस्पोजेन्ट संख्या 01 से 5 मौके पर काबिज काश्त है तथा लगान सरकारी अदा करते आ रहे है। विवादित आराजीयात पक्षकारान की पैतृक एवं मौरुशी मुश्तर्का आराजीयात रही है जिस पर पक्षकारान अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। रेस्पोजेन्ट संख्या 03 रेस्पोजेन्ट संख्या 01 व 2 के पिता है विवादित आराजीयात रेस्पोजेन्टगण के स्व. दादा व पिता रूपसिंह की खातेदारी की आराजीयात रही है इस प्रकार विवादित आराजी रेस्पोजेन्ट संख्या 01 व 2 की पैतृक आराजीयात रही है जिसमें रेस्पोजेन्ट संख्या 03 के नाम दर्ज आराजीयात में रेस्पोजेन्ट संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, रेस्पोजेन्ट संख्या 2 को 1/3 हिस्सा एवं रेस्पोजेन्ट संख्या 3 का 1/3 हिस्सा है रेस्पोजेन्टगया का विवादित आराजीयात में बाई बर्थ हिस्सा है जिस पर वे शांतिपूर्वक आराजी का बाहमी बंटवारा कर पक्षकारान हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। विवादित आराजी का मौके पर बंटवारा नहीं हो रखा है तथा रेस्पोजेन्ट संख्या 3 जो कि रेस्पोजेन्ट संख्या 01,2 के पिता है जो अपने भाईयों के बहकावों में आकर विवादित आराजीयात में रेस्पोजेन्ट संख्या 01, 2 को उनके हक व हिस्से की आराजीयात से महरूम रखते हुए सम्पूर्ण आराजी का बोन करने पर आमादा है। जिसका रेस्पोजेन्ट संख्या 3 को कोई अधिकार नहीं है। दिनांक 25.05.2019 को रेस्पोजेन्ट संख्या 3 से 05 के साथ दीगर व्यक्ति वादग्रसत आराजीयात को इन दीगर व्यक्तियों को दिखा रहे थे जब रेस्पोजेन्ट संख्या 01,2ने इसका कारण पूछा तो रेस्पोजेन्ट संख्या 3 से 5 ने रेस्पोजेन्ट संख्या 01,2 को ऐलानिया धमकी दी कि वादग्रस्त आराजी को वह उक्त दीगर व्यक्तियों को बिना तकासम</p>	

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

लगान

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

340/19/225

श्री. राजू लाल यादव vs श्री. अशोक सिंह

<p>तारीख पेशी</p>	<p>2019/00340 हुकम या कार्यवाही मय हस्ताक्षर</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुकम की तामील जारी हुए</p>
<p>श्री</p>	<p>श्री</p>	<p></p>
<p>2019/12/12</p>	<p>करवाये ही बेचान करेगे तथा रेस्पोजेन्ट संख्या 01, 2 को उनके हिसे व कब्जे काश्त से बेदखल करेगे। रेस्पोजेन्ट संख्या 01,2 को अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने एवं रेस्पोजेन्ट संख्या 03 से 05 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11.06.2019 को अप्रार्थीगण जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करते हुए विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश दिये है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 11.06.2019 से असंतुष्ट होकर अपीलांत ने यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।</p> <p>अभिभाषक अपीलांत ने आगे बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 11.06.2019 न्याय, नियम एवं विधि के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोजेन्ट संख्या 01 व 2, रेस्पोजेन्ट संख्या 3 के पुत्र-पुत्रियों है तथा उन्हें आराजीयात के विक्रय का सम्पूर्ण ज्ञान है उसके बावजूद क्रेता को पक्षकार कायम नहीं किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय को मुगालता देते हुए अपील प्रस्तुत कर एक तरफा स्थगन प्राप्त किया है। पिता के जीवनकाल में पुत्र-पुत्रियों का हिस्सा नहीं होता है उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है। स्थगन आदेश की आड़ में रेस्पोजेन्टसगण ने दुरभी संधी के तहत वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्थगन प्राप्त कर लिया है जबकि उक्त वाद एवं प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में अपीलार्थी को पक्षकार कायम किया जाना था चूंकि उक्त प्रकरण में अपीलार्थी का हित निहित है जिससे अपीलार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू के आदेश दिनांक 11.06.2019 की क्रियान्विति ताफैसला अपील स्थगित किये जाने के आदेश प्रदान करावे। अभिभाषक अपीलांत ने अपने पक्ष में आर.आर.टी.2017(2) पेज 1362 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया गया हैं।</p> <p>अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों व अपीलाधीन आदेश की प्रति व अपील मीमों व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू के आदेश दिनांक 11.06.2019 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को आगामी आदेशों तक विवादित आराजी को राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश पारित किये है। अभिभाषक अपीलांत ने उक्त आदेश दिनांक 11.06.2019 की अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की हैं। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण वास्ते इन्तजार नोटिस अप्रार्थी संख्या 01से 5 हेतु नियत हैं तथा अपीलांत ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण में पक्षकार संयोजित होने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया तथा ना ही अपना जवाब प्रस्तुत कर आपत्ति प्रकट नहीं कर उक्त अन्तरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील न्यायालय हाजा में पोषणीय नहीं है तथा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं। न्यायहित में माननीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर के आदेश दिनांक 14.07.2010 बउनवानी हुकुम सिंह बनाम राज्य सरकार (आर.आर.टी. 2011 पेज 01) के न्यायिक दृष्टांत को मध्यनजर रखते हुए एवं पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, हम अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र का 60 दिवस में उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर निर्णित करें।</p> <p>सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को अभिभाषक अपीलांत के प्रस्तुत कथन एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए स्वीकार किया जाता हैं तथा अपीलांत का अपील प्रस्तुत करने की अनमति दी जाती है एवं अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।</p>	<p></p>

अजमेर अपील प्राधिकारी

2019/12/12

